the time of commencement of DPCO, 1979 and what was the price notified by Government for these drugs; and

(d) what steps have been taken to investigate the bungling?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (d) The DPEA liabilities against M/s Merind and Cadila in respect of bulk drug Dexamethasons and its formulations have been assessed, on tentative basis, for the entire period of DPCO, 1979 and the same has been communicated to both the companies. At present, both these cases are pending before the Drug Prices Liabilities Review Committee constituted by the Department to get the entire matter relating to the DPEA recoveries reviewed by it. Government can take further course of action only after receipt of the Reports of the said Committee in both the cases.

उर्वरक क्षेत्र के लिए ऋण

1088. श्री गोपाल सिंह चौलेकी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक क्षेत्र के लिए ऋणों का प्रावधान इसकी आवश्यकता से कहीं कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान उर्वरक क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश का प्रतिशत क्या है;

(घ) इस क्षेत्र की आवश्यकता की तुलना में उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कुल कितनी पूंजी उपलब्ध कराई गई;

(ङ) इस क्षेत्र में कम पूंजी निवेश किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(छ) 1999-2000 के दौरान इस क्षेत्र के लिए पूंजी की कुल अनुमानित आवश्यकता क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) और (ख) उर्वरक परियोजनाएं शुरू करने तथा कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क करने की जिम्मेवारी उर्वरक उद्योग के प्रवर्तकों/उद्यमियों की है। जहां तक उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों का संबंध है, वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराये गये ऋण इस प्रकार हैं:—

(रुपये करोड़)

वर्ष	योजनागत	योजनाभिन्न	योग
1996-97	250.71	440.34	691.05
1997-98	191.38	406.49	597.87
1998-99 (संशोधित अनुमान)	180.88	400.00	580.88

(ग) से (छ) उर्वरक उद्योग अत्यधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग है जिसकी स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:—

(i) नये संयंत्रों की स्थापना करने/मौजूदा संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत मामलों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर।

(ii) उर्वरक कच्चे मालों तथा मध्यवर्तियों का रियायती दर पर आयात।

(iii) उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं की संभावित निर्यात लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली पद्धति के तहत की जायें।

(iv) पोषकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत।

(v) वर्तमान में यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य सह-सब्सिडी स्कीम के तहत उद्यमियों को निवेश पर लाभ की मुनासिब दर।

(vi) मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का रेट्रोफिटिंग/पुनरुद्धार।

(vii) नेफथा पर आधारित विस्तार परियोजनाओं की स्थापना करके तथा मौजदा संयंत्रों और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में दोहरी

ईंधन/फीडस्टाक सुविधाओं की स्थापना करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाइयों पर काबू पाना, तथा

(viii) प्रचूर तथा सस्ते कच्चे माल के स्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना

वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों में योजनागत व्यय इस प्रकार है:—

वर्ष	रु० करोड़
1996-97	2153.96
1997-98	1314.61
1998-99	957.32

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों के लिए वर्ष 1999-2000 तक की अवधि हेतु 1822.50 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव किय गया है।

Package for Bengal

1089. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned, "Package for Bengal announced", appearing Business Standard, Calcutta, of 11th February, 1999, regarding revival of Hindustan Fertilizer Corporation (HFC);

(b) if so, whether Government have concretised revival plan of Durgapur and Haldia units of HFC in West Bengal for submission to BIFR; if so, the salient features of the same; and

(c) if not, the reasons therefor in view of the public announcement of the same on 10th Februrary, 1999?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. PATEL): (a) Yes, Sir. It refers, inter-alia, to the revival of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. (HFC) which stands referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR).

(b) and (c) A revival package for HFC was initially formulated in the year 1995 which envisaged a limited revamp of its functional units. The Government decided to close/hive off the Haldia Project of HFC. Thereafter, an Expert Group, under the leadership of ICICI, was constituted to reformulate the package and it submitted its report in 1997. The Government of consideration of the report, approved the revival package in respect of Namrup units only and deferred the decision in respect of other units of HFC including its Durgapur unit. Proposals regarding other units of HFC based on their techno-economic viability will be submitted to the competent authority in the Government and final sanction of BIFR, which is a quasi-judicial authority.

Demands of IDPL Workers

1090. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken on the demands of the workers of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited;

(b) if so, the details of revival/ rehabilitation package; and

(c) the steps taken for payment of monthly salary to the employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. PATEL): (a) and (b) A package for the revival of IDPL approved by BIFR on 10.2.1994 was implemented w.e.f. 1.4.1994. The same, however, failed in the first year of